रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1984/कार्तिक 19, 1906

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1984/KARTIKA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

(आयकर)

का० आ० 3568.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि ताज एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली, उसके द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा के लिये प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल, तक विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उन्हें सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी ।

संस्था

ताज एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 11-2-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5726 (फा० सं० 203/136/82-आ. क० नि० II]

मदन गोपाल चन्द गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th March, 1984

INCOME-TAX

S.O. 3568.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Taj Agricultural Research Centre, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research;

(ii) That the said centre will furnish Annual Return of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year;

(iii) That the said centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total Income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Taj Agricultural Research Centre, New Delhi.

This notification is effective for a period from 11-2-1984 to 31-3-1985.

[No. 5726 (F. No. 203/136/82-ITA.II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3569.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली में सचिव श्री आर. गोपालस्वामी को श्री मोहिन्द्र सिंह के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक नियुक्त करती है।

[सं०एफ० 7/2/84-बी. ओ०-1]

च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3569.—In pursuance of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Shri R. Gopalaswamy, Secretary in the Ministry of Rural Development, New Delhi as the Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development vice Shri Mohinder Singh.

[No. F. 7/2/84-BO.I]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3570.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियों) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 के प्रावधान राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर को 30 जून, 1983 को समाप्त वर्ष को उसके तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख तक लागू नहीं होंगे।

[सं० फा० 8-14/84-ए० सी०]

अमर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3570.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provision of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Co-operative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Rajasthan State Industrial Co-operative Bank Ltd., Jaipur so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30th June, 1983 together with the auditors report in a newspaper.

[F. No. 8-14/84-AC]

AMAR SINGH, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1984

(आयकर)

का. आ. 3571.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 17-4-1982 की अपनी अधिसूचना सं. 4579 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम सं. 21-ङ और 21-च के सामने स्तम्भ 4 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
21-ङ	मदुरै	मदुरै	16. विशेष सर्वेक्षण रेमंडल (प्रथम ायकर अधि-री, द्वितीय यकर अधि-री) मदुरै।
21-च		कोयम्बटूर	शेष सर्वेक्षण 19. रेमंडल म आय-अधिकारी, य आयकर कारी), म्बटूर।

यह आदेश 10-9-1984 से लागू होगा ।

[सं० 5961(फा० सं० 187/14/84-आ. (नि० I]

CENTRAL BOARD OF DIRECT T

New Delhi, the 6th September, 198

INCOME-TAX

S.O. 3571.—In exercise of the powers co by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax 61 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes he makes the following amendments to its Notification 79 dated 17-4-1982.

The following entries shall be added unde4 against Sl. No. 21-E and 21-F.

SCHEDULE

S. No.	Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdict
1	2	3	
21-E	Madurai	Madurai	16. Survey Circles O, 2nd ITO rai.
21-F	Coimbatore	Coimbatore	19. Survey Circles, O, 2nd ITO atore.

This Order shall take effect from 10-9-1

[No. 5961 (F. No.4-IT(AI)]

का. आ. 3572.—आयकर अधिनि 961 की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वा 8 जून, 1984 की अपनी अधिसूचना सं० 5859 (फा० सं० 187/14/84-आ० क० (नि०-1) के क्षेत्राधिकार स्तंभ के अंतर्गत मद 8(ii) और (iii) की प्रविष्टि का लोप करता है ।

[सं० 5962 (फा० सं० 187/14/84-आ०क० (नि०-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

S.O. 3572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby deletes the entry at item 8(ii) and (iii) under column jurisdiction of its Notification No. 5859 [F. No. 187/14/84-ITAI)] dated the 8th June, 1984.

[No. 5962 (F. No. 187/14/84-IT(A)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

Central Board of Direct Taxes

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1984

का० आ० 3573.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स दी इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में विनिर्मित स्टील ट्यूब का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स दी इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 43, चौरंगी रोड कलकत्ता-700071 में स्थित है, 16 मई 1984 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का० आ० 1491 तारीख 16 मई 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फाइल सं 5(8)/80-ईआई एण्ड ईपी]

एन० एस० हरिहरण, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th November, 1984

S.O. 3573.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1984. M/s. The Indian Tube Company Limited, having their registered office at 43, Chowringhee Road, Calcutta-700071, as the agency, for inspection of steel tubes manufatured at M/s. The Indian Tube Company Limited, Jamshedpur, prior to export. subject to the conditions notified vide S.O. 1491 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(8)/80/EI & EP]

N. S. HORIHARAN, Director

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

हैदराबाद, 22 अक्तूबर, 1984

रद्द करने का आदेश

का०आ० 3574.—अप्रैल 82 मार्च 83 की आयात नीति के अनुसार फिनाल के आयात के लिए मैसर्स अमित पोलिमर्स और काम्पोसिटरस लिमिटेड, सर्वेक्षण सं० 335 और 336, चितकुल ग्राम, संगारेड्डी तालुका (मेदक जिला) को रुपये 4,00,000 के सि० आई० एफ० मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2228120/सि/XX/86/डब्ल्यू/82 दिनांक 1-2-83, जारी किया गया था। अब पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की

दूसरी प्रति के लिए इस कारण आवेदन किया है कि उन दोनों की मूल प्रतियां गलत जगह पर रख दी गई है। अब जो सीमा शुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की दूसरी प्रतियों की आवश्यकता है उसका मूल्य कुल 4,00,000 होगा।

अपने दावे के समर्थन में आवेदनकर्ता ने मोहरयुक्त कागज पर नोटरी प्रमाणक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दायर किया है। आवेदनकर्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की मूल प्रतियों का पता लग जाने पर/मिल जाने पर उसे लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को लौटा दिये जायेंगे।

मुझे संतुष्टि हुई है कि लाइसेंस सं० पी/डी/2228120 दिनांक 1-2-83 की सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की मूल प्रति गलत जगह पर रख दी गई है और आवेदनकर्ता को सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की दूसरी प्रतियां जारी किये जाएं। इसके द्वारा लाइसेंस सं० पी/डी/2228120 दिनांक 1-2-83 की सीमा शुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की मूल प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[मिसिल सं० आई टी सी/ए यू/डी जी टी डी/138/ए एम 83/ हैदराबाद]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

Hyderabad, the 22nd October, 1984

CANCELLATION ORDER

S.O. 3574.—M/s. Amit Polymers and Composites Ltd., Survey Nos. 335 and 336, Chitkul village, Sangareddy Tq. (Medak Dt.) were granted an import licence bearing No. P/D/2228120/C/XX/86/W/82 dated 1-2-83 for a c.i.f. value of Rs. 4,00,000 for import of Phenol as per Import Policy for the period April 82—March 83. The party has applied for grant of duplicate Customs and Exchange Control copies of the aforesaid import licence on the ground that both the copies of the licence have been misplaced. The total amount for which the duplicate Customs & Excange Control copies of the licence are required for a value of Rs. 4,00,000.

In support of their contention, the applicant has filed an affidavit on stamped paper duly attested by a Notary. The applicant has also undertaken to return the licensing authority concerned the original Customs and Exchange Control copies of the licence, if the same are traced or found later on.

I am satisfied that the original Customs and Exchange Control copies of licence No. P/D/2228120 dated 1-2-83 have been misplaced and that duplicate Customs and Exchange Control Copies of licence should be issued to the applicant. The original Customs and Exchange Control copies of licence No. P/D/2228120 dated 1-2-83 are hereby cancelled.

[No. ITC/AU/DGTD-138/AM 83/Hyd.]

रद्द करने का आदेश

का०आ० 3575.—अलंकारिक कागज तथा फिल्टर कागज के आयात के लिए मैसर्स अमित पोलिमर्स और काम्पोसिटरस लिमिटेड, सर्वेक्षण सं० 335 और 336, चितकुल ग्राम, संगारेड्डी ताल्लुका (मेदक जिला) को अप्रैल 82 से मार्च 83 व आयात नीति के अनुसार रु० 10,50,000 के सि० आई० एफ० मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2223090/सि/20/85/डब्ल्यू/82 दिनांक 5-11-82, जारी किया गया था। अब पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय की दूसरी प्रति के लिए इस कारण आवेदन किया है कि मुद्रा विनिमय की मूल प्रति गलत जगह पर रख दी गई है। अब जो दूसरी प्रति की आवश्यकता है उसका मूल्य कुल रु 2,86,156 (केवल दो लाख, छियासी हजार, एक सौ छप्पन रुपये) होगा।

अपने दावे के समर्थन में आवेदनकर्ता ने मोहर युक्त कागज पर नोटरी प्रमाणक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दायर किया है। आवेदन कर्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि मुद्रा विनिमय की मूल प्रति का पता लग जाने पर/मिल जाने पर लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

मुझे संतुष्टि हुई है कि लाइसेंस सं० पी/डी/2228090 दिनांक 1-82 की मुद्रा विनिमय की मूल प्रति गुम गई/गलत जगह पर रख दी गई है और आवेदनकर्ता को मुद्रा विनिमय की दूसरी प्रति जारी की जाये : इसके द्वारा लाइसेंस सं० पी/डी/2228090/दिनांक 5-11-82 की मुद्रा विनिमय की मूल प्रति रद्द की जाती है।

[मिसिल सं० आई टी सी/ए यू/डी जी टी डी/138/ए एम 83/ हैदराबाद]

आर० सेलवराज, उप मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात

CANCELLATION ORDER

S.O.—M/s. Amit Polymers and Compositors Ltd., Survey 335 and 336, Chitkul Village, Sangareddy Tq. (Med.) were granted an import licence bearing No. P/D/?0/C/XX/85/W/82 dated 5-11-82 for a c.i.f. value 10,50,000 for import of Decorative Paper and Filter as per Import Policy for the period April 82—March The party has applied for grant of duplicate Exchange Control copy of the aforesaid import licence on the that the original Exchange Control copy of the has been misplaced. The total amount for which duplicate copy of the licence is required for a value 2,86,156 (Rs. Two Lakhs, Eighty Six Thousand, One Hundred and Fifty Six only).

In support of their contention, the applicant has filed an affidavit stamped paper duly attested by Notary. The applicant has also undertaken to return the licensing authority concerned the original Exchange Control copy of licence if the same is traced or found later on.

I am satisfied that the original Exchange Control copy of No. P/D/2228090 dated 5-11-82 has been lost/misplaced and that duplicate Exchange Control copy of licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control copy of licence No. P/D/2228090 dated 5- hereby cancelled.

[No. ITC/AU/DGTD-138/AM.83/Hyd.]

R. SELVARAJ, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3576—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासण-29 से सोभासण-15 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोभासण-29 से सोभासण-15 तक पाईप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य-गुजरात जिला और तालुका—मेहसाना

गांव	स नं	हैक्टयर	एआरई	सेन्टीयर
हेबुवा	244	0	00	50
	201	0	19	20

(सं० 0-12016/108/84-ओ०एन०जी०-डी०-4)

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 23rd October, 1984

S.O. 3576.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sobhasan-29 to Sob-15 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from DS Sobhasan-29 to SOB-15

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	244	0	00	50
	201	0	19	20

[No. O-12016/108/84-ONG-D4]

का० आ० 3577:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस०ई०जेड० से एस०ई०जी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिय एतद्द्वारा अनुसूची, में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस०ई०जेड० से एस०ई०जी० तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला और तालुका—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं	हैक्टेअर	ए आर ई	सेंटीअर
कुकस	724	0	36	60
	738	0	29	28
	740	0	03	12
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	748	0	06	00
	23	0	12	96
	20	0	15	96
	21	0	12	24
	कार्ट ट्रेक	0	01	08
	155	0	06	24
	157/2	0	02	64

[सं०-0-12016/109/84-ओ०एन०जी०-डी० 4]

S.O. 3577.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SEZ to SEG in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from S.E.Z. to S.E.G.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kukas	724	0	36	60
	738	0	29	28
	740	0	03	12
	Cart track	0	00	60
	748	0	06	00
	23	0	12	96
	20	0	15	96
	21	0	12	24
	Cart track	0	01	08
	155	0	06	24
	157/2	0	02	64

[No. O-12016/109/84-ONG-D4]

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1984

का०आ० 3578 :—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एनोड बेड और वायर बेड बिछाने के लिये पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एनोड बेड और वायर बेड बिछाने के लिय ।

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गांव	ब्लाक नं	हैक्टेअर	ए आर ई	सैंटीअर
मोटी भोपन	1060	0	00	30
	1059	0	00	34
	1058	0	00	36
	1057	0	00	16
	1051	0	00	70
	1052	0	01	40
	1940	0	02	10

[सं० O-12016/107/84-ओ०एन०जी०-डी० 4]

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1984

S.O. 3578.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Anode Bed to Wire Bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Right of Users for Anode bed & Wire Bed
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Moti Bhoyan	1060	0	00	30
	1059	0	00	34
	1058	0	00	36
	1057	0	00	16
	1051	0	00	70
	1052	0	01	40
	1940	0	02	10

[No. O-12016/107/84-ONG-D.4]

P. K. RAJ GOPALAN, Desk Officer

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3579—केन्द्रीय सरकार, गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4, उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 क, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मोहन नायर के स्थान पर श्री जो इंजीनियों डायस को मुरगांव डाक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2969 दिनांक 10 अगस्त, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में "गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक में मद सं. (3) के आगे "श्री मोहन नायर" के स्थान पर "श्री जो इजीनियों डायस" रहेंगे ।

[फाइल सं. एल डी जी/6/84-यू. एस. (एल)]

वी० शंकर लिंगम, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 3579.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri Joe Eujeino Dias as a member of the Mormugao Dock Labour Board vice late Shri Mohan Nair and for that purpose makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 2969 dated the 10th August, 1982, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Dock Workers", against item No. (3), for the entry "Shri Mohan Nair", the entry "Shri Joe Eujeinio Dias" shall be substituted.

[F. No. LDG/6/84-US(L)]

V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

का०आ० 3580—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड (III) के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कविलन्डी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/84-पी एच बी]

यी०रा० भसीन, महा निदेशक (पी एच बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 23rd October, 1984

S.O. 2580.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs hereby specified 16-11-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Quilandy Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-9/84-PHB]

Y.R. BHASIN, Asstt. Director General (PHB)

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3581—केन्द्रीय सरकार, बीडी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) के साथ पठित बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुय मध्य प्रदेश राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :-

1. श्रम मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल । — अध्यक्ष

2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन नेपियर टाऊन, जबलपुर ।	उपाध्यक्ष पदेन
3. श्रमायुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश	सदस्य
4. श्री शिवकुमार श्रीवास्तव विधान सभा सदस्य सागर ।	सदस्य
5. श्री बाबुराव पिम्पलापुर, भागीदार- मैसर्स बृजलाल मणिलाल एंड कम्पनी, सागर	नियोजकों के प्रतिनिधित्व
6. श्री बी. वी. शुक्ला महासचिव, बी. पी. बीड़ी उद्योग संघ जबलपुर ।	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. डा. एल. एन. सिल्हाकारी, अध्यक्ष, बीड़ी मजदूर संगठन, सागर ।	कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व
8. श्री श्यामलाल चौबे, अध्यक्ष जिला बीड़ी मजदूर संघ दमोह (म्युनिस्पेलीटी बिल्डिंग) नया बाजार संख्या 1 दमोह ।	
9. श्रीमती मंजुदेवी, विधान सभा सदस्य, सेहोरा, जबलपुर ।	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण प्रशासक, जबलपुर ।	सचिव

2. केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन जबलपुर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय निर्धारित करती है।

[संख्या यू-19012/4/83-डब्ल्यू II]

MINISTRY OF LABOUR
(Department of Labour)
New Delhi, the 20th October, 1984

S.O. 3581.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Madhya Pradesh consisting of following members, namely:—

1. Labour Minister, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.	Chairman
2. Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Napier Town, Jabalpur	Vice-Chairman ex-Officio
3. Labour Commissioner, Indore, Madhya Pradesh.	Member.
4. Shri Shivekumar Shrivastave, M.L.A., Sagar	Member.
5. Shri Baburao Pimplapure, Partner M/s Brijlal Manilal & Co., Sagar	Employers' representatives
6. Shri B.V. Shukla, General Secretary, M.P. Bidi Udyog Sangh, Jabalpur.	
7. Dr. L.N. Silhakari, President, Bidi Mazdoor Sangthan, Sagar.	Employees' representatives
8. Shri Shyamlal Chobey, President, Zilla Beedi Mazdoor Sabha, Damoh (Municipality Building), Naya Bazar No. 1, Damoh.	
9. Smt. Manjudevi, M.L.A., Sehora, Jabalpur.	Women representative
10. Welfare Administrator, Jabalpur.	Secretary

2. Under rule 16 of the said rules, the Central Government hereby fixes Jabalpur to be the headquarter of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/4/83-W. II]

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3582.—केन्द्रीय सरकार बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उपनियम "2" के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :—

1. श्रम मंत्री तमिलनाडु सरकार मद्रास ।	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, 1-7-145, प्लाट सं. 6, श्री निवास कालोनी, सुभाष टाकीज के सामने, हैदराबाद-500048.	उपाध्यक्ष पदेन
3. उप श्रमायुक्त (निरीक्षण) श्रमायुक्त का कार्यालय, मद्रास-6	सदस्य
4. श्री कुलसेकरपांडियन, राज्य विधान सभा, वानियाम्वदी, 15 सनांनकुप्पम, ट्रंक रोड, अम्बुर इन० ए० जिला	सदस्य
5. श्री ए० मोहम्मद अशरफ, उपाध्यक्ष, तमिलनाडु बीड़ी मैन्युफक्चरर्स, एसोशियेशन वलौर।	नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री थीरू अबदुल धानी, अध्यक्ष, मद्रास प्रोविंशयल बीड़ी फैक्टरी ऑनर्स एसोशिएसन, मद्रास ।	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री एम० नम्बिराजन, उपाध्यक्ष, अन्ना थोजिरसांगा पेरवाई, मद्रास ।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री थीरू वी. देसियामनीकन्नम, महासचिव, नार्थ अर्कोट जिला, नेशनल बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन, (इन्टक), वैल्लुर ।	
9. थीरूमति कस्थुरी बालन, 6, नेहरू नगर, अम्बातुर, मद्रास-53	महिला प्रतिनिधि
10. सहायक कल्याण आयुक्त, मदुराई ।	सचिव

2. केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हैदराबाद को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है ।

[संख्या यू-19012/5/83-डब्ल्यू II]

कंवर राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd October, 1984

S.O. 3582.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Govt. hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Tamil Nadu consisting of the following members namely:—

1. Labour Minister, Govt. of Tamil Nadu, Madras.	Chairman
2. Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation 1-7-145/Plot No. 6 Srinivasnagar Colony, Opposite Subhas Talkies, Hyderabad-500048.	Vice-Chairman-ex-officio
3. Deputy Commissioner of Labour (Inspection), Office of the Commissioner of Labour, Madras-6.	Member.
4. Thiru Kulasekarapandian, Member of State Legislature, Vaniyambadi, 15, Sanankuppam Trunk Road, Ambur, N.A. District.	Member.
5. Thiru A. Mohmmed Asraf, Vice-President, Tamil Nadu Beedi Manufacturers' Association, Vellore.	Employers' Representatives
6. Thiru Abdul Ghani, President, Madras Provincial Beedi Factory Owners' Association, Madras.	
7. Thiru S. Nambirajan, Vice-President, Anna Thozhirsanga Peravai, Madras.	Employees' Representatives
8. Thiru V. Desiyamanikannan, General Secretary, North Arcot District National Beedi Workers' Federation (INTUC) Vellore.	
9. Thirumathi Kasthuri Balan, 6, Nehru Nagar, Ambattur, Madras-53.	Women representative
10. Assistant Welfare Commissioner, Madurai.	Secretary

2. The Central Government in exercise of powers conferred by rule 16 of the said rules, hereby fixes Hyderabad as the headquarters of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/5/83-W. II]

KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3583.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Ludhiana and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No I.D. 4/84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank, Nangal Township—Punjab.

AND

Their Workman—Amar Nath Malik.

ACTIVITY : Banking STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 12th October, 1984

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, per their Order No. L-12012/262/83-D.II(A), dated the 6th of February, 1984 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Ludhiana in reltaion to their Nangal Township Branch in not allowing Sh. Amar Nath Malik, Clerk-cum-Cashier to officiate in the post of Special Assistant/Accountant as and when the need for such officiating chances in stop-gap arrangements

arose during the period from 7-10-78 to 30-6-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. In all fairness to them, the Management responded favourably to a suggestion floated by the Tribunal for a reconsideration of the petitioner's cause and thus agreed to pay him a consolidated amount of Rs. 450 (four hundred and fifty only) in full and final settlement of his claim. The offer was accepted by the petitioner—workman.

3. It grew without saying that the aforesaid terms are favourable to the petitioner/workman since by necessary implication, his stand in vindicated and the claim is satisfied almost in its entirely. Accordingly, on approving the same, I return my Award in the terms mentioned herein before.

Chandigarh, 12-10-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer.

[No. L-12012/262/83-D.II(A)/D.IV(A)]

New Delhi, the 25th October, 1984

S.O. 3584.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Naresh Nath Mookherjee and their workman, which was received by the Central Government.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 22 of 1983

PARTIES:

Employer in relation to the management of M/s. Naresh Nath Mookherjee

AND

Their Workman.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCE:

On behalf of Management—Mr. N. C. Das Sharma, Advocate.

On behalf of Workman—Mr. M. S. Dutta, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port & Dock

AWARD

By Order No. L-32012/1/83/D-IV(A) dated 11th March, 1983, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation referred the following dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of Messrs Naresh Nath Mookherjee, 6 Clive Row, Calcutta-1 in terminating the services of Shri Mohitosh Chatterjee, Accountant with effect from 16-7-81 is justified ? If not, to what relief is he workman entitled ?"

2. The concerned workman has filed a petition that he will not proceed further and the reference may be dropped. It is a reference under section 2A, read with section 10(1)(d). The concerned workman, therefore is fully competent to file this application. In view of this state of affairs Mr. Dutta who appears for the concerned workman submits that he has now nothing to say. It follows that there is no longer any industrial dispute.

Accordingly let a no dispute award be passed.

Dated, Calcutta, 27th August, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-32012/1/83-D.IV(A)]

S.O. 3585.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the National Insurance Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th October, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISTH, PRESIDING OFIFCER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 12 of 1979 (N. Delhi) 8 of 1983 (Chd.)

PARTIES

Employers in relation to the Management of National Insurance Company.

AND

Their Workman—Sh. Amar Singh.

APPEARANCES :

For the Employers—Sh. Kashmira Singh.

For the Workman—S/Sh. Rajindra Dhawan and M. L. Basur.

ACTIVITY : Insurance Company Union Terriory Chandigarh.

AWARD

Dated, the 11th October, 1984

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-17012(13)/78/D-IV(A) dated the 21st of March, 1979, read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adrudication—

"Whether the action of the management of National Insurance Company Limited in not giving chance for re-employment to Shri Amar Singh, Ex-Peon, while making regular appointments in the sub-staff category, as per Section 25-H of the Industrial Disputes, Act, 1947 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. During the course of hearing I floated a suggestion to the Management to reconsider the petitioner's cause for an opportunity of re-employment as a model of social justice in view of the compassion that he was out of job ever since his termination by them. In all fairness to them, they responded favourably and without prejudice to the merits of the case, offered to give him preferential treatment at the time of fresh recruitments in their subordinate staff against the first available vacancy, provided he was sponsored by an Employment Exchange. The offer was accepted by the petitioner/Workman with a reservation in the sense that simple registration in the Employment Exchange should suffice the requirement because the provisions of the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act does not apply to subordinate staff vacancies.

3. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the parties I am inclined to sustain the petitioner Workman's prayer that instead of insisting on a formal sponsorship by the Employment Exchange the Management should feel contended with the incident of his registration with the said agency; because the formality of sponsorship is something beyond his control, and then one cannot loose sight of the fact that the parties are entering into a one time settlement without any liability to suffer precedent.

4. Accordingly, I return my Award in favour of the petitioner/Workman with a direction to the Management to accord him a preferential treatment in the matter of re-employment against the first available vacancy in their subordinate staff in any of their branches of Chandigarh Division. He would be called for interview and considered on merits alongwith other candidates in the usual manner but without any insistence on being sponsored by an Employment

Exchange of course he should be on the live register of the Exchange on the day of his interview as well as appointment in the event of selection.

Chandigarh, 11-10-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-17012/13/78-D.IV(A)]

K. J. D. PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3586--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूपा इंडस्ट्रीज, सी-30, इंडस्ट्रीयल एस्टेट गुंडी, मद्रास-600032, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि, प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, और 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019(440)/84-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3586.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Rupa Industries, C-30, Industrial Estate, Guindy, Madras-600032 Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(440)/84-PF.II]

का० आ० 3587.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टिपटाप ब्रियानी एंड मील्ज होटल, 8 कालेज रोड, तिरुपुर-638602, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[एस०-35019(441)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 3587.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Tip Top Briyani and Meals Hotel, 8, College Road, Tiruppur-638602, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(441)/84-PF.II]

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3588—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

गुरदासपुर जिले में निम्नलिखित राजस्वग्राम :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त संख्या
1.	कण्डियाल	218
2.	खातिब	243
3.	हरदो धण्डा	288
4.	शाहब पुरा	212
5.	बटाला ईस्ट	211
6.	बाखवाल	214
7.	कुतब नांगल	216
8.	किला टेक सिंह	217
9.	गोखेवाल	242
10.	सुनया	284
11.	सैयद मुबारक	297

[संख्या एस-38013/17/84-एस.एस-I]

New Delhi, the 23rd October, 1984

S.O.3588.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th October, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.
1.	Kandyal	218
2.	Khatib	243
3.	Hardo Jhanda	288
4.	Shahab Pura	212
5.	Batala East	211
6.	Bakhewal	214
7.	Kutbi Nangal	216
8.	Quila Tek Singh	217
9.	Gokhewal	242
10.	Sunaya	284
11.	Sayed Mubark	297

in the District of Gurdaspur.

[No. S-381013/17/84-SS-I]

का. आ. 3589--मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास-89 (तमिल नाडु 5573) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014/91/84-एस. एस.-4]

S.O. 3589.—Whereas Messrs Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Nand Ambakkam, Madras-89 (TN/5573) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features therof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/91/84-SS-IV]

का. आ. 3590.--मैसर्स एस. के. इंडस्ट्रीज, 151 इंडस्ट्रीयल एरिया जयपुर-302021 (आर. जे. 2265) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/92/84-एस०एस०-4]

S.O. 3590.—Whereas Messrs S. K. Industries, 151, Industrial Area, Jaipur-302012 (RJ/2265) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the maority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment *exempted under the said Act, is employed in* his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/92/84-SS-IV]

का०आ० 3591—मैसर्स अलवर भरतपुर ग्रामीण बैंक भरतपुर (आर०जे०/3647) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम, के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं; या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/93/84-एस० एस-4]

S.O. 3591.—Whereas Messrs Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank, Bharatpur (RJ/3647) (hereinafter referred to the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the opertaion of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of he Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/93/84-SS-IV]

का०आ० 3592.—मैसर्स इंडियन एलोमिनियम कं० लि० बान्दगढ़-9 (एम एच/13349) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा

17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले ही अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[स० एस-35014/95/84-एस०एस-4]

S.O. 3592.—Whereas Messrs Indian Aluminium Company Limited, Chandgad-416509 (MH/13349) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making

any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the opertaion of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/95/84-SS-IV]

का० आ० 3593.—मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कं० लि० बेलापुर रोड, कलवा थाना (एम एच/616) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/96/84-एस०एस०-4]

S.O. 3593.—Whereas Messrs Indian Alluminium Company Limited, Belapur Road, Kalwa Thana-400605 (MH/910) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the opertaion of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/96/84-SS-IV]

का०आ० 3594—मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कं० लि०, पोस्ट बाक्स स० 5, तलोजा, एम्बी० 410208 जिला रायगढ़ (एम०एच०/1971) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन, जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों, का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे

किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/97/84-एस.एस.-4]

S.O. 3594.—Whereas Messrs Indian Alluminium Co. Ltd., Post Box No. 5, Taloja A.V. 410208, Distt. Raigad (MH/11971) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the opertaion of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the maority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is ligely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects."

[No. S-35014/97/84-SS-IV]

का. आ. 3595.—मैसर्स ग्लक्सो लैबोरेट्रीज इंडिया लि., मंजूरगढ़ी, अलीगढ़-202001, यू.पी. (यू.पी. 928) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन

फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, यू.पी. को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा जीवन स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों के कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, यू.पी. के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/98/84-एस.एस.-4]

S.O. 3595.—Whereas Messrs. Glaxo Laboratories (India) Ltd., Manzurgarhi Aligarh-202001 UP/936, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Noice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/98/84-SS. IV]

का. आ. 3596.—मैसर्स विशफोर्ट फोग लि. 67, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, एम. आई. डी. सी., सतपुर, नासिक (एम.एच. 14845) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षणों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/99/84-एस. एस.-4]

S.O. 3596.—Whereas Messrs Viscorts, Forge Limited, 67, Industrial Estate M.I.D.C. Satpur, Nasik, (M.S.) (MH/14845), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/99/84-SS-IV]

का.आ. 3597.—मैसर्स ब्राईट ब्रादर्स लि० एल० बी० एस० मार्ग, भांडुप बम्बई-78 (एम. एच. 5001) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारियों को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[स. एस-35014/100/84-एस.एस.-4]

S.O. 3597.—Whereas Messrs. Bright Brothers Limited, L.B.S. Marg, Bhandup, Bombay-78 (MH/5001) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/100/84-SS-IV]

का. आ. 3598.--मैसर्स इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड वीरभद्र-2 (यू. पी. 3556) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, यू. पी. को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त यू. पी. के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं.एस.-35014/102/84-एच. एस.-4]

S.O. 3598.—Whereas Messrs. Indian Durgs and Pharmaceuticals Limited, Virbhadra-240202 (Rishikesh) (UP/3556), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. Al-l expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/102/84-SS-IV]

का. आ. 3599.--मैसर्स नागअर्जुना स्टील लिमिटेड, हैदराबाद (ए. पी./6630) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन, बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक हों जो उक्त स्कीम के अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस.-35014/104/84-एस.एस.-4]

S.O. 3599.—Whereas Messrs. Nagarjuna Steels Limited, Nagarjuna Hills Panjagutta, Hyderabad (AP/6630), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/104/84-SS-IV]

का. आ. 3600.—मैसर्स थम्बी मॉडर्न सिपिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमलूर रोड, जागीर अम्मापालयम, सलीम-636302 (टी.एन./10265) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन सामूहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या स.-35014/107/84-एस. एस.-4]

S.O. .—Whereas Messrs. Thambi Modern Spinning Mills Private Limited, Omalur Road, Jagir Amma Palayam, Salem-636302 (TN/10265), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submitt such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/107/84-SS-IV]

का. आ. 3601.—मैसर्स श्री वर्धराजा टेक्सटाईल प्राइवेट लिमिटड, पो. बोक्स नं. 1616 कोम्बटूर (टी० एन० 519) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस०-35014/108/84-एस. एस.-4]

S.O. 3601.—Whereas Messrs Sri Varadaraja Textiles Private Limited, Post Box No. 1616, Peelamedu, Coimbatore-641004 (TN/519), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and

provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect".

[No. S-35014/108/84-SS-IV]

का. आ. 3602.—मैसर्स कोयम्बटूर पाईनर फरटीलाईजर्स लि. मुनुकौन्डनपुदूर पोस्ट (मार्फत) सलूर-6, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट (टी. एन./5639) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधियिनम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/109/84-एस. एस.-4]

S.O. 3602.—Whereas Messrs Coimbatore Pioneer Fertilizers Limited, Muthugoundenpudur Post, (Via) Sulur-641406, Coimbatore Distt. (TN/5639), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect".

[No. S-35014/109/84-SS-IV]

का० आ० 3603:—मैसर्स अनील स्टील और इन्डस्ट्रीज लि. पो. बाक्स नं. 174 कल्यापुरा जयपुर 302001 (आर. जे./1674) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों। जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम

निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/110/84-एस. एस.-4]

S.O. 3603.—Whereas Messrs. Anil Steel and Industries Limited, P. B. No. 174, Kanakpura, Jaipur-302001 (RJ/1674), (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect".

[No. S-35014/110/84-SS-IV]

का. आ. 3604.—मैसर्स असट्रा-आईडल लि. क्रिसन्ट टावर 32/1-2, क्रिसन्ट रोड, पो बोक्स नं 5039, बंगलौर (कै.एन./241) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं:

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारी को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014/112/84-एस. एस.-4]

S.O. 3604.—Whereas Messrs Astra-Idl. Limited, Crescent Towers, 32/1-2, Crescent Road, P.B. No. 5039, Bangalore-1 (KN/241) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/112/84-SS-IV]

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3605.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"रंगारेड्डी जिला के राजेन्द्र नगर तालुक में सिवरामपल्ली, अट्टापुर (उत्तर), गगन पहाड़ (दक्षिण), अट्टापुर, अलीबाग, मैलार डेनपल्ली, बोम रुक नुडोवल (पूर्व) तथा पद्मावतीपेट, बोम-रुक नुडोवला, बुदवेल (पश्चिम) के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत कट्टेडम का क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/18/84-एस. एस-1]

New Delhi, the 25th October, 1984

S.O. 3605.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th October, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The area of Kattedan within the revenue villages of Sivarampally, Attapur (North), Gaganpahad (South) Attapur, Ali Bagh, Mailar Denapally, Bom-Ruk-Nuddowla (East) and Padmavatipate, Bom-Ruk-Nuddowla, Badwel (West) in Rajendra Nagar Taluk of Rangareddy District."

[No. S-38013/18/84-SS-I]

का. आ. 3606.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी साउदर्न पेस्टीसाइडस कारपोरेशन लिमिटेड, 10-5-3/2/2 मसब टैंक, हैदराबाद- 500028 और कोवूर, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्स, आन्ध्र प्रदेश स्थित ब्रांच सहित नाम स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/393/84-पी० एफ-2]

S.O. 3606.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Southern Pesticides Corporation Limited, 10-5-3/2/2 Mesab Tank, Hyderabad-500028 and its branch distt. Kovvur, West Godavari (District) Andhra Pradesh have agreed that provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(393)/84-PF. II]

का. आ. 3607.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेरामाउन्ट इंजीनियरिंग कारपोरेशन 5, कालमापुरम स्ट्रीट, मद्रास-2 तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/394/84-पी. एफ-2]

S.O. 3607.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Paramount Engineering Corporation, 5, Kalimanpuram Street, Madras-2, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(394)/84-PF.II]

का. आ. 3608.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माईक्रो वेव सिस्टम्स एण्ड कम्पोनेंटस (प्रा०) लिमिटेड, शान्ति नगर हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/395/84-पी. एफ-2]

S.O. 3608.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Micro Wave Systems & Components (P) Ltd. Shanti Nagar Hyderabad (Andhra Pradesh) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(395)/84-PF.II]

का. आ. 3609:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स "मंगल दीप" विमल्स शो रूम कोठी हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/396/84-पी. एफ-2]

S.O. 3609.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. "Mangal Deep" Vimal's Show Room, Kothi, Hyderabad, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(396)/84-PF.II]

का. आ. 3610:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि ईस्ट अभिरामापुरम वोमैन्स कन्जूमर्स को-आपरेटिव स्टोर्स लि., जैड एन. सी. 664, नं. 49, III स्ट्रीट मैलापोर, मद्रास 4, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/397/84-पी. एफ०-2]

S.O. 3610.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The East Abiramapuram Women's Consumers' Co-operative Stores Ltd., XNC. 664, No. 49, III Street, Maylapore, Madras-4, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(397)/84-PF.II]

का. आ. 3611:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटो एजेन्सीज 2698 लोथियन रोड कश्मीरी गेट दिल्ली-110006 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/398/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3611.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Auto Agencies, 2698, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(398)/84-PF.II]

का० आ० 3612.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मास प्रैस ए. बी. -4 सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली 16 नाम स्थापन के सम्बन्द्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/399/84 पी. एफ. -2]

S.O. 3612.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Mass Press, AB-4, Safdarjung Enclave, New Delhi-110016 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(399)/84-PF.II]

का. आ. 3613:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गायत्री पेस्टीकेम 81/4 जी. आई. डी. सी. वतवा-45 जिला अहमदाबाद (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस- 35019/400/84-पी. एफ. -2)]

S.O. 3613.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Gayatri Pestichem, 81/4, G.I.D.C., Vatva-45 District, Ahmedabad (Gujarat) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(400)/84-PF.II]

का. आ. 3614.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. टी. लेखाडिया लेखाडियावादी सिन्धी शेरी सलाबतपुर सूरत (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं. एस- 35019/40/84-पी. एफ. -2]

S.O. 3614.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M. T. Lekhadia Lekhadiawadi Sindi Sheri Salabatpura, Surat (Gujarat) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(401)/84-PF.II]

का. आ. 3615.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माडर्न टायर मौल्ड्स (इंडिया) प्र. लि. सी-210/2, मायापुरी फेस-II नई दिल्ली-14 और रजि. आफिस 1, भगत सिंह स्ट्रीट दिल्ली 55 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस- 35019/402/84 पी०-एफ०-2]

S.O. 3615.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Modern Tyre Moulds (India) Pvt. Ltd., C-210/2, Mayapuri Phase-II New Delhi-64 including regd. office at 1, Bhagat Singh Street, New Delhi-55 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Govenment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(402)/84-PF.II]

का. आ. 3616.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बीके प्रोजेक्ट कन्सलटेंट्स (प्रा०) लि०, सी-4/43 सफदरजंग डीवलेपमेंट एरिया नई दिल्ली-16 और ब्रांच आफिस कैम्प नं-2 भिलाई (म. प्र.) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019/403/84-पी. एफ-2]

S.O. 3616.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Beckay Project Consultants (P) Ltd., C-4/43, Safdarjang Development Area, New Delhi-16 and Branch Office at Camp No. 2, Bhilai-490001 (M.P.) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(403)/84-PF.II]

का. आ. 3617.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेडीटोनिक्स कारपोरेशन, 4098 12-बी, दरिया गंज, नई दिल्ली 110002 नामक स्थापन के सम्बन्द्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 1) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध के उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं. एस-35019/404/84-पी. एफ-2]

S.O. 3617.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Meditronix Corporation, 4598/12-B, Darya Ganj, New Delhi-110002 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(404)/84-PF.II]

का. आ. 3518.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चोकसी ट्यूब्स कम्पनी लि. प्लाट नं. 60/ए वतवा इंडस्ट्रीयल एरिया बटवा- 332445 अहमदाबाद (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/405/84-पी. एफ-2]

S.O. 3618.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Choksi Tubes Company Ltd., Plot No. 60/A, Vatva Industrial Area Vatva-382445, Ahmedabad (Gujarat), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(405)/84-PF. II]

का. आ. 3619.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पन्ना लाल टंडन प्रा. लि. 10-11 सुन्दर नगर, मार्किट नई दिल्ली-3 और शाखा शेड नं. 63 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया कम्पलैक्स फेज-1 नई दिल्ली में स्थित नामक स्थापन के नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं. एस-35019/406/84-पी० एफ-2]

S.O. 3619.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Pannalal Tandon Pvt. Ltd.. 10-A, Sunder Nagar Market, New Delhi-3 and branch at shed No. 63, Okhla Industrial Area Complex, Phase-II, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(406)/84-PF-II]

का. आ. 3620--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटोमेशन सी-319 फेज-II मायापुरी नई दिल्ली-14 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि औ प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं. एस- 35019/407/84-पी. एफ-2]

S.O. 3620.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Automation, C-319, Phase-II, Mayapuri, New Delhi-64 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(407)/84-PF. II]

का. आ. 3621.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 10707 सिकल को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक लिमिटेड सिक पोस्ट नागापत्तिनाम तन्जौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा को उप-धारा 4 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (422)/84-पी. एफ2.]

S.O. 3621.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. 10707, Sikkal Co-operative Agricultural Bank Ltd.. Sikkal Post, Nagapattinam, Tanjore District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(422)/84-PF. II]

का०आ० 3622.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी. थन्गारासु, वेनिविलास, विनाई मार्ग, चेरुट, कुड्डालोर-2, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(426)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3622.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. C. Thangarasu, Vanivilas, Veenai Mark, Cheroot, Cuddalore-2, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(426)/84-PF. II]

का.आ. 3623.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि सादर्न प्रेशर कास्टिंग्स नं. 36 (एन पी) इकाटू थानगल, मद्रास-97 और 14 ए (एस.पी.) इन्डस्ट्रियल स्टेट, मद्रास-32 स्थित प्रशासन कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(427)/84/पी-एफ-2]

S.O. 3623.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Southern Pressure Castings, No. 36 (N. P.) Ekkattu Thangal, Madras-97 including Administration Office at 14-A (S. P.) Industrial Estate, Madras-32 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(427)/84-PF. II]

का.आ. 3624.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रिमपैक नं. 81, ए.आर. रामासामी रोड, कुम्बाकोनम-612002, तमिल नाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(428)/84 पी०एफ.-2]

S.O. 3624.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Trimpak No. 81, A. R. Ramasami Road, Kumbakonam-612002, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(428)/84-PF. II]

का.आ. 3625—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयजयाम ट्रेडिंग एण्ड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड, 33, मूरे स्ट्रीट, मद्रास-600001 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लागू करती है।

[सं० एस-35019(429)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3625.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jayjayam Trading & Agency Pvt. Ltd. 33, Moore Street, Madras-600001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(429)|84-PF. II]

का.आ. 3626—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री जी एन्टरप्राइजेज 56 सिडको इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कोइम्बटूर, 641021, तमिल नाडु, और 16-बी डी० बी० रोड, आर.एस. पुरम, कोइम्बटूर-2, स्थित प्रशासन कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः उक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(430)/84/पी-एफ-2]

S.O. 3626.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Srijl Enterprises, 56, Sidco Industrial Estate, Coimbatore-641021, Tamil Nadu and its Administrative Office at 16-B, D. B. Road, R. S. Puram, Coimbatore-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(430)|84-PF. II]

का.आ. 3627—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोका प्रकाश एन्टरप्राइजेज, 49, थन्डावाराया ग्रामिणी स्ट्रीट, मद्रास-21, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(431)/84/पी.एफ.-2]

S.O. 3627.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Asokaprakash Enterprises, 49, Thandavaraya. Gramani Street, Madras-21, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act. the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(431)|84-PF. II]

का.आ. 3628—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर.एन. सामी, जावुली स्टोर्ज, 8-9, सथ्या मूर्थि रोड, आरनी-632301, नार्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(432)/84/पी.एफ-2]

S.O. 3628.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. R. N. Samy. Javuli Stores, 8-9, Sathyamoorth Road, Arni-632301, North Arcot District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(432)|84-PF. II]

का.आ. 3629—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुन्दर एण्ड कम्पनी, क्लीयरिंग एण्ड फोरवर्डिंग एजेंट्स, फर्स्ट फ्लोर, 22, जोन्स स्ट्रीट, मद्रास-600001, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(433)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3629.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sunder & Co., Clearing & Forwarding Agents, 1st Floor, 22, Jones Street, Madras-600001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(433)|84-P.F. II]

का.आ. 3630—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिकॉन इंडस्ट्रीज, सी-2, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, कृष्णगिरी 635001, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(434)84-पी.एफ.-2]

S.O. 3630.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Unicorn Industries, C-2 SIDCO Industrial Estate, Krishnagiri-635001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(434)|84-P.F. II]

का.आ. 3631—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इनलेण्ड एजेंसीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 110, गोरल मर्चेन्ट्स स्ट्रीट, मद्रास-600001, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(435)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3631.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Inland Agencies (Pvt.) Ltd., 110, Goral Merchants Street, Madras-600001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(435)|84-P.F. II]

का.आ. 3632—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होलवार्ट इंजीनियरिंग कंपनी, 430, माउन्ट रोड, मद्रास-37 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(436)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3632.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Holwart Engineering Co., 430, Mount Road, Madras-35 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(436)|84-P.F. II]

का.आ. 3633—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डायमण्ड इंडस्ट्रीज एण्ड केमिकल सेल्स, 60, साउथ राजा स्ट्रीट, टूटीकोरन-628001, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(437)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3633.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Diamond Industries & Chemical Sales, 60, Sourth Raja Street, Tuticorin-628001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(437)|84-P.F. II]

का० आ० 3634.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भवानासी इंजीनियरिंग कंपनी, नं 24, बेऊर रोड भवानासी-7 638654, कोईमबटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1962 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(438)/84-पी० एफ० 2-]

S.O. 3634.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Avanashi Engineering Co., No. 24, Cheyor Road, Avanashi-638654 Coimbatore District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(438)|84-P.F. II]

का० आ० 3635.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैशाली बार, 1773, केलकारबाग, बेलगाम, कर्नाटका, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

सं० एस-35019(454)/84/पी०एफ 2]

S.O. 3635.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs. Vaishali Bar, 1773,, Kelkarbag, Balgaum, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(454)/84-PF. II]

का० आ० 3636.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कंदन टाकीज, चेटपेट-606801 रोलुर तालुक, नार्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा, 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(455)/84/पी०एफ-2]

S.O. 3636.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kandan Talkies, Chetpet-606801, Rolur Taluk, North Acrot District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(455)/84-PF. II]

का० आ० 3637.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० आर० जी० परसनल नेटवर्क प्रा० लि०-405 सरस्वती हाउस 27, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-19 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (456)/84 पी० एफ०-2]

S.O. 3637.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs ARG. Personnel Net Work Pvt. Ltd., 405, Saraswati House, 27, Nehru Place, New Delhi-110019 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(456)/84-PF. II]

का० आ० 3638.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्रो ब्रेक्स लिमिटेड, 14/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा और 29 कम्युनिटि सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सहित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[एस-35019 (457)/84 पी० एफ०-2]

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

S.O. 3638.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Crau Brakes, Limited, 14/6, Mathura Road, Faridabad, Haryana including its Regd. Office at 29, Community Centre, East of Kailash, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(457)/84-PF. II]

CHITRA CHOPRA, Director

New Delhi, the 25th October, 1984

S.O. 3639.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra, New Delhi, and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th October, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 69/81

In the matter of dispute between :

Ram Parshad S/o Shri Kanhaiya Lal, working at Bank of Maharashtra, Connaught Place, New Delhi through Union of the Maharashtra Bank Employees (Regd.), Delhi Unit 898, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi-6;

Versus

Bank of Maharashtra C/o Connaught Place, New Delhi, C/o The Asstt. General Manager, Bank of Maharashtra Northern Zone, Asaf Ali Road, Hoechest House, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri J. P. Amodekar—for the Management.

Shri R. K. Kadam—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 21-5-81 vide Order No. L-12012(164)/80-D.II.A made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, New Delhi in not taking into account the temporary employment(s) of Shri Ram Parshad as part of his probationary period is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Ram Parshad joined as Peon at Connaught Place branch of the Bank of Maharashtra, New Delhi w.e.f 24-9-75. His services were utilised in the same branch of the bank from 24-9-75 to 13-10-76 with breaks of two to five days in between in November, 75, January 76, May 76, August 76 and October 76. He was put on probation w.e.f. 19-10-76.

3. The workman's case is that artificial breaks in his service were mala fide and improper and that he continued to be in continuous service on permanent post; and he should be treated as on probation w.e.f. 24-9-75 and also get wages for illegal and abrupt 19 days' break in service. He claims annual graded increments ever since 24-9-75 with all arrears and other benefits like bonus, leave, provident fund etc. w.e.f. 24-9-75.

4. The Management of Bank of Maharashtra contested the claim and asserted that the workman was appointed against temporary post and as and when necessary and when he was appointed permanently, he was put on probation.

5. The evidence has been recorded and the arguments of the parties have been heard.

6. Mr. K. V. Kulkarni, Manager, Bank of Maharashtra filed affidavit for the Management and stated that Ram Parshad was appointed w.e.f. 19-10-76 in the vacancy in U.P.S.C. Extension counter which started functioning in January, 1977 and earlier to that he worked on temporary basis.

7. Apart from the word of Mr. K. V. Kulkarni in his affidavit, no evidence is there to show that the vacancy was temporary and the breaks in service of Ram Parshad Peon at Connaught Place are only of two of five days' duration during the whole period 24-9-75 to 13-10-76 and these breaks do not indicate a break in renovation work pleaded by the Management at the Connaught Place Branch. Mr. K. V. Kulkarni had to admit that Ram Parshad was not a watch-man and renovation work continued and did not end with each termination of Ram Parshad's service.

8. It appears that the workman's argument is correct and the breaks in service were given artificially and without reason, and the persons recruited later than Ram Parshad peon were made senior to him, Ram Singh was made permanent before Ram Parshad, while Ram Singh joined service after 24-9-75 and the saving bank account Number of Ram Singh is later than the saving bank account number of Ram Parshad.

9. It seems to be a fact tha the services of Ram Parshad were utilised by the Management almost continuously from 24-9-75 and the artificial break of 19 days during a period of more than a year is under some impression of the bank not to grant continuity to the workman.

10. It would be fair and proper to accept the workman's contention that his service with the bank of Maharashtra in the Connaught Place Branch was continuous, despite breaks, and it would be further proper to treat him on probation w.e.f. the date of his initial appointment in the service on 24-9-75 and not from 19-10-76, as the Management has done. This would be in accordance with the judgement of the C.G.I.T. Bombay No. 2 in CGIT-2/11 of 1971 published in Gazette of India dated 28-4-73 pages 1667 to 1671 extract from which reads as under :—

"......As a general rule, the temporary employment is not counted and is not taken into account as part of the probationary period. The provisions contained in para 20.8 makes a departure from this rule. This para introduces a legal fiction that if a temporary workman is eventually selected for filling up the permanent vacancy, the period of temporary employment will be taken into account as part of probationary period. By virtue of this provision 20.8 Shri H. K. Soni is entitled to contain that the period of his temp. employment since 2-12-66 should be taken into account as part of his probationary period. ...."

11. I hold that the action of the Management of the bank of Maharashtra in excluding the earlier service of Ram Parshad Peon from probationary period is incorrect and unjustified and that Ram Parshad should be treated as on probation as a peon from 24-9-75 and not w.e.f. 19-10-76 but he need not be paid for the day of artificial breaks when he did not work. However he shall be entitled to graded increments for the year 1976 and thereafter treating him to be on probation w.e.f. 24-9-75. He is also entitled to arrears of salary on that basis and also to say other benefits like seniority and bonus which may be due to him on that foundation. Award is made accordingly.

Further ordered that the requisite number of copies of Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

October 11, 1984.

O. P. SINGLA, Presiding Officer.
[No. L-12012/164/80-D.II(A)]

S.O. 3640.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra, New Dehi, and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th October, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA ; PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI.

I.D. N. 165|81

In the matter of dispute between :

Shri Trilok Singh Peon, B|o Connaught Place, New Delhi, Through Union of Maharashtra Bank Employees.

Versus

Bank of Maharashtra B/o Connaught Place, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri R. K. Kadam—for the workman.

Shri J. P. Amodekar—for the Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 13-11-81 vide Order No. L-12012|272|80-D.II.A made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in relation to its Branch at Connaught Place, New Delhi in not treating Shri Trilok Singh, Peon on probation with effect from 17-9-74 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Mr. Trilok Singh worked at the Karol Bagh South Extension and Connaught Place Branches of Bank of Maharashtra, New Delhi. He worked from 17-9-74 to 14-12-74 at Karol Bagh Branch with breaks from 15-12-74 to 19-12-74. He worked at South Extension Branch from 26-12-74 to 12-2-75 with breaks from 13.2.75 to 16.2.75 and worked at Connaught Place Branch from 6-5-75 to 6-6-75 and had breaks from 17-3-75 to 5-5-75 and 7-6-75 to 8-6-75. He was put on probation w.e.f. 9-6-75 at the Connaught Place Branch as sub-staff.

3. His case is that the vacancies were permanent and the breaks illegal and that he is entitled to be treated as probationary-peon from 17-9-74 and confirmed after service of six months. He also claimed wages for illegal breaks and annual graded increments for the years 75-76 and so on as also other benefits including bonus, leave, P.F. medical leave and uniform.

4. The management of Bank of Maharashtra contested the claim and asserted that his employment was against temporary vacancies and the breaks in his service were for that reason. It was pleaded that the Bank did not violate any term of the Bank Awards and he was rightly treated as a probationer w.e.f. 9-6-75.

5. The evidence has been led and arguments of the parties' representatives have been heard.

6. The plea of the workman is that the Management indulged in unfair labour practice and the Management violated the provisions of para 522(4) of Shastry Award, which allowed temporary employees engaged in indefinite period to one month salary and allowance. The Management was also said to have violated Bipartite Settlemet dated 19-10-66, paras 20.7 and 20.8, because the Bank could not prove that service of temporary employees were utilised against temporary vacancies, on account of temporary increase of work or in connection with temporary additional load of work or in place of any absent workman. Para 20.8 is specifically referred to where it is mentioned that temporary employment should not exceed a period of three months, in case of permanent vacancies.

7. A decision of Central Govt. Industrial Tribunal No. 2 Bombay in CGIT-2|11 published in the Gazette of India dated 28-4-73 pages 1667 to 1673 is referred to and the following extract is quoted:

"......As a general rule, the temporary employment is not counted and is not taken into account as part of the probationary period. The provisions contained in Para 20.8 makes a departure from this rule. This para introduces a legal fiction that if a temporary workman is eventually selected for filling up the permanent vacancy, the period of temporary employment will be taken into account as part of probationary period. By virtue of this provision 20.8 Shri N. K. Soni is entitled to contain that the period of his temporary employment since 2-12-66 should be taken into account as part of his probationary period...".

8. Industrial Dispute Act, 1947 Vth Schedule annexed to section 2(ra) by amendment in 1982 mentions unfair labour practices and at item No. 10 it is unfair labour practice to employ workmen as "badlis" casuals or temporaries and to continue them as such for years, with the object of depriving them of the status and privilages of permanent workmen.

9. It is a question of fact whether the employment of this workman as temporary for the period 17-9-74 to 6-6-75 was by way of unfair labour practice or otherwise.

10. The period of this workman's service at Karol Bagh was only for three months, at South Extension branch for less than two months and be remained temporary at Connaught Place branch only for one month. These temporary appointments of his for very short periods do not appear to be by way of unfair labour practice and the Management of the Bank of Maharashtra does not seem to be guilty in that respect.

11. Regular recruitment in the Bank employment is a public employment because the Bank is a "STATE" under Article 12 of the Constitution of India and the Indian Citizens have a right to equal chance of employment under Article 16 of the Constitution of India. It is not contended that the vacancies where this workman worked in temporary capacity were of regular nature for which applications were invited from other Citizens of India also giving them equal chance of employment alongwith him.

12. The action of the Bank of Maharashtra in treating him as on probation w.e.f. 9-6-75 does not call for any interference and appears to be justified. The award is made accordingly.

Further ordered that the requesite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No.L-12012/272/80-D.IIA]

N. K. VERMA, Desk Officer.

October 11, 1984.

New Delhi, the 29th October, 1984

S.O. 3641.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Commandant 510, Army Base Workshop, Meerut Cantonment and their workmen which was received by the Central Government on the 10th October, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NEW DELHI

I.D. No. 21/79

In the matter of dispute between :

Shri Kashmiri Lal Sharma S/o Late Pandit Mehnga Ram, Resident of 'Hari Niwas' Courts Road, Hoshiarpur (Pb.).

Versus

Army Base Workshop, 510, Meerut Cantt-250001 through the Commandant 510, Army Base Workshop.

APPEARANCES :

Shri Narinder Chawdhary—for the Management.

Shri A. K. Sikri Advocate—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-14012(1)/78-II(B) dated 26th April, 1979 made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Commandant, 510, Army Base Workshop; Meerut Cantonment in reverting Shri Kashmiri Lal Sharma from the post of 'A' Grade Clerk/Upper Division Clerk to the post of 'B' Grade Clerk/Lower Division Clerk firstly with effect from the 1st January, 1948 and subsequently with effect from the 20th January, 1949, is justified ? If not; to what relief is the said workman entitled ?"

2. Mr. K. L. Sharma retired from 510, Army Base Workshop on 30th April, 1979. He was employed as Lower Division Clerk on 23-6-43 in Head Quarter S.P.C.R, at Ferozpur, now known as ASC Records (Supply) Bangalore.

3. M. K. L. Sharma was promoted as UDC on 1-9-44. He was reverted w.e.f. 1-1-48 and was transferred to records office Bengal Engineering Group, Roorkee in July, 1950 and from there again to ASC Records (Supply), Bangalore in September, 52 and from there to industrial installation 510, Army Base Workshop, Meerut Cantt. in August, 59. He was again promoted as UDC on 1-10-61 and was confirmed w.e.f. 1-4-66.

4. The workman Mr. K. L. Sharma was reverted w.e.f. 1-1-48 from A Grade Clerk|UDC to B Grade Clerk|LDC vide Order dated 5-1-48 "owing to reduction in establishment".

5. The workman pleaded that his reversion was the result of victimisation and the action was not bona fide. Reference is made to the report "he was reported 'Dud' and not suitable for employment as UDC and was therefor reverted. He is still not suitable for promotion and his case cannot be recommended". This assertion is made by the employer in the endorsement made on his representation dated 25-10-49 addressed to O.I.C. R.I. ASC Records (Supply) by the workman. The word 'Dud' in the terminology of the employer means 'inefficient person'.

6. The workman continued to represent against his reversion and, ultimately, an order was made by President of India on 9-10-68 setting aside his reversion w.e.f. 1-1-48, and ordering him to be given seniority from 1-1-48 but dssallowing arrears of salary from the date prior to the date of issue of the order. It also denied him promotions with retrespective effect under para 2 of Ministry of Home Affairs O.M. No. 9/49/54-R.P.S. dated 25th April, 1958.

7. The claim of the workman is that, when the order of reversion w.e.f. 1-1-48 was nullity, he could not be deprived of arrears of salary and other benefits including promotions due to him, and that the President did not give him any hearing before passing the said order depriving him arrears of pay prior to the date of issue of the order on 9-10-68 and other benefits.

8. Later, another order was made on 28-2-70 that the workman stood reverted to the post of LDC w.e.f. 20-1-49. This order, besides being malicious, is said to be void and inoperative because it is made by an authority lower than that of the President of India who has passed the earlier order setting aside reversion, and the order of the Preident of India could not be superseded by any Lower Authority and this order was passed without opportunity to the workman to make his submissions.

9. The workman claimed that he had been victimised for no fault of his and had been denied arrears of salary and promotion due to him. He claimed that he was entitled to arrears of salary and promotion, when his juniors got promotion. He claimed that he would have become Head Clerk Grade II from 1-5-62 HC Grade I from 15-9-65 and Civilian Gazetted Officer from 23-5-66. He has claimed amounts due to him on the basis of such promotions, as also pension, gratuity and other concessions as if those promotions were granted to him. He has also claimed 12% per annum interest on the amounts due to him. He has also asked overtime allowance for overtime work permitted. Arrears of pay and allowances claimed vide Schedule I in the statement amount to Rs. 76309.75 p. Rs. 961.96 are claimed as arrears of overtime, and Rs. 3,21,676.79 p. are claimed as interest.

10. The Management of Army Base Workshop contested the claim that Mr. K. L. Sharma was industrial worker was not admitted. It was said that he was not a 'workman' as the term is defined in I.D. Act, 47. He was said to have served in 510, Army Base Workshop Meerut Cantt. w.e.f. 24-8-59 and retired on 30-4-79. He was said to be as L.D.C. in H.Q. S.P.C.R., Ferozpur and his service from 23-6-43 to 23-8-59 could not be said to be a service in an Industrial Establishment. He was said to have been posted from ASC Records (Supply) Bangalore to 510 Army Base Workshop, Meerut Cantt, on the own request as a Lower Division Clerk from 24-8-59. He was promoted to the post of Head Clerk in Grade II w.e.f. 23-12-69, a supervisory post.

11. The reversion on 1-1-48, which was amended to 20-1-49 was before the Constitution of India came into force on 26-1-50 and, therefore, any reference of Constitution of India was irrelevant. He was neither appointed nor reverted by the Commandant, 510, Army Base Workshop, Meerut Cantt. He was appointed and reverted by OIC ASC Records (Supply) who was the competent authority.

12. The workman was said to be an inefficient clerk and was not suitable for promotion to the post of UDC by OIC ASC Records (Supply).

13. The order of the President of India, vide letter No. 24(24)/61/D. (Lab.) dated 9th October, 68, setting aside his reversion w.e.f. 1-1-48 while he was serving in ASC Records (Supply) had to be dealt with under para 2 of Ministry of Home Affairs OM. dated 25-4-58, and his seniority and pay was regulated accordingly. Arrears of pay and allowances not admissible under that order. Mr. K. L. Sharma could not claim arrears of pay nor promotions under that order, and that order was final. No comments could be offered against the order passed by the President of India, the Constitutional Head of the State. There was said to be no second reversion of workman in 1970. Simply the date of first reversion was amended by ASC Records D.O. dated 28-2-70. The Labour Court, Kanpur had held that application of the workman was not maintainable, and this Tribunal was said to have no jurisdiction.

14. On behalf of the workman an application was made to Government of India on 30-8-83 for amendment in the terms of reference pending before this Tribunal. The Government of India vide No. L-14012(1)/78-D II (B) dated 24th January, 1984 addressed to Office Secretary, Azad Karamchari Sangh, Army Base Workshop 223-Shakpuri, Kankar Khera, Meerut Cantt. (U)-250001 (with copy to K. L. Sharma and also to this Tribunal) ordered as under :—

"No. L-14012(1)/78-D. II(B) Government of India/ Bharat Sarkar Ministry of Labour and Rehabilitation (Shram Aur Punarwas Mantralaya) Department of Labour/Shram Vibhag.

New Delhi, the 25th January, 1984

To

The Office Secretary,

Azad Karamchari Sangh,

Army Base Workshops,

223-Shakpuri, Kankur Khera, Meerut Cantt. (U)-250001.

Subject.—Application for amendment of the terms of reference Schedule to this Ministry's Order No. L-14012 (1)|78-D.II(B) dated the 26th April, 1979.

Sir,

With reference to your application date the 13th August, 1983 I am directed to say that the workman was employed in an industrial establishment and relief for him has been sought by the Union in terms of the Industrial Disputes Act, 1947. Under the said enactment the legal terms used are the employer and the workman and accordingly the Commandant, 510 Army Base Workshop being the employer was rightly made the party in the terms of reference. No change in the name of the party in the terms of reference is considered necessary.

2. The Union has further requested that the terms of reference be amended in such a way so that the Presidential Order referred to in the representation regarding payment of wages is also included. The terms "If not to what relief is the said workman entitled" specified in the terms of reference is broad enough to cover whatever relief the Tribunal considers just in the context of its findings on the dispute. Thus, any amendment to the terms of reference already notified is not considered necessary.

Yours faithfully,

Sd/-

(T. B. SITARAMAN)
Desk Officer"

16. The following issue was settled by my Ld. Predecessor in office on 3-12-80.

1. As in terms of reference.

17. The amendment had been allowed earlier to the Management in the written statement para 9. The earlier para 9 was in the following terms :—

"That the contents of para 9 of the plaint are not admitted. Shri Kashmiri Lal Sharma was reverted being DUD (inefficient) by the sole-Judge viz. ASC Records, the appointing authority of Shri Kashmiri Lal Sharma. His reversion is unchallengeable."

This was amended and paras 9 and 10 thereafter read as under :

Para 9

"That the contents of para 9 of the plaint are not admitted. Shri Kashmiri Lal Sharma was reverted due to reduction in establishment and further promotion was not given to him being DUD (inefficient) by the sole Judge viz. ASC Records the appointing authority of Shri Kashmiri Lal Sharma. His reversion is unchallengeable."

Para 10

"The contents of para 10 of the plaint are not admitted. Shri Kashmiri Lal Sharma was reverted being an inefficient clerk."

18. The matter in reference has been tried and oral and written arguments of the parties have been examined carefully. The evidence on record has been scrutinised.

19. Even though there is no specific issue the question of the claimant being a workman and the applicability of I. D. Act, 1947, these may be examined first.

20. The Ld. Advocate for the Management has referred to B. K. Bharti and another Vs. State of Bihar and others. (A Full-bench decision of Patna High Court) reported in 1983 Lab. I. C. 1884 to assert that, when Civil Service Rules are applicable, the applicability of the I. D. Act, 47 is excluded. The decision is rather to be contrary Para 7 of the judgement may be reproduced as under :

"If there are enactments, or rules framed under Art. 309 of the Constitution, which either expressly or by necessary implication exclude the operation of the Industrial Disputes Act, no question of applicability of the provisions of the Act arises. The mere fact that there is service Code dealing with some of the aspects of the employer-employee relationship between the Government and its Employees does not amount by necessary implication to the exclusion of the provisions of the Act to Government Departments. If there were Rules for instance, specifically dealing with the manner in which temporary appointments could be terminated, it could legitimately be argued that S 25-F of the Act is excluded. For then, the rules framed under the constitutional provisions would have precedence over the provisions of the Act. It is not possible to accept the extreme contention, that the provisions of the Industrial Disputes Act do not at all apply to Government Servants."

21. In this case, the applicability of I D. Act, 47 is not excluded by reference to any provisions of Civil Service Rules specifically.

22. As regards the question whether the claimant is a 'workman', he retired as a Head Clerk and being a Head Clerk does not make his position supervisory. The Azad Karamchari Sangh Union is of all Army Base employees, and non-industrial employees cannot be members of this Union, and Mr. K. L. Sharma was a member of this Union only because he was 'workman' under the I. D. Act, 47. He was not cross-examined on the point that his duties were supervisory, when the workman was subjected to cross-examination on 23-9-81. The claimant in his affidavit, had stated clearly that he never performed any supervisory duty. It is held that the claimant Mr. K. L. Sharma did not have a supervisory duties and is included in the definition of 'workman' under the I. D. Act, 47.

23. The technical objection that the reversion w.e.f. 1-1-48 was not by Commandant 510 Army Base Workshop, Meerut Cantt but by ASC Records (Supply) is answered by the order of the Government of India dated 25-1-84 reproduced earlier.

24. Shri Narinder Chaudhary Advocate for the Management relied on three matters for justifying the action against the workman. The first ground is that the reversion was on account of workman's own request and consent. The second ground is that the action was by way of 'reduction in establishment' and the individual opinion or statement of any officer is irrelevant. The third ground taken is that the order of the President of 9-10-68 must be read as a whole and cannot be effective in part, and the claimant is estopped from challenging the Presidential order under which he seaks benefit.

25. The workman gave his consent to his reversion fearing retrenchment on the ground of shrinkage in strength of the establishment. But later it turned out that there was to be no shrinkage and, in fact, not only reverted earlier but even persons reverted upto 24th January, 49 were restorad to their positions. It is at this stage that the workman submitted his representation for being given back the post of UDC, which he had to vacate from 1-1-48. When the matter came before his officer Capt. Kartar Singh, he made the following remarks on the representation dated 25-10-49 of the workman.

"The statement of the applicant vide para 2 is not correct. He was reported as 'DUD' and not suitable for employment as upper division clerk and was therefore reverted. Para 4 also not correct. He is still not suitable for promotion and his case cannot be recommended. Application has been seen by the SRO and the case has been discussed. No further action necessary. Inform the applicant and file."

26. These remarks out-off the case of the workman in terms of RIAS'C records (Supply) instruction No. 16 of 1949, para 4. The instruction is in the following terms :—

"RIASC Records (Supply) Instruction No. 16 of 1949."

R.O.I. No 16 Pay and Allowances-Civilian Clerks RIASC

Reference R.O.I. No. 11/49, Para 2. It has been decided that all civilian clerks of the RIASC (including JCOs on status), will receive pay in accordance with Civilians in Defence Services (Revision of pay) Rules 1947 as reproduced in IAO 192/48. No individual will draw Unified Scale of Pay beyond 31 December, 1947.

2. Pending fixation of proportion between Upper and Lower Division Civilian Clerks (including JCOs on Status), who were in Gde 'A'/UD on 1 January 1948, are placed provisionally in the Upper Division and those who were in B and C grades are placed in the Lower Division w.e.f. that date.

3. OSC Units will take necessary action to fix the initial pay of civilian clerks in the UD or LD, as the case may be, in direct communication with the CMA concerned. Action in respect of JCOs on status will betaken in communication with DFCMA i/c FPO RIASC (Supply) Bangalore-7.

4. If any clerk was reverted from Grade 'A'/UD to 'B' or 'C' grade or LD on or after 1 January, 1948 for inefficiency or misconduct, he will receive the pay of the Lower Division w.e.f. the date of such reversion.

5. The date of election of the prescribed scale by civilian personnel including JCOs on status has been extended upto 31 March 1949 vide IAO 150/49.

"(Auth : Ministry of Defence Memo. No. 2(3)654/D-11 dated 20-1-49 and Indarmy Signal No. 416660/Q/ST 5 dated 11 March 49)".

27. The result of Capt. Kartar Singh's action was that the workman was deemed to have been reverted on account of inefficiency and could not get the benefit of repromotion w.e.f. 1-1-1948.

28. It is in this light that the matter has to be examined. The reversion of the workman must be treated to be on account of his inefficiency because, if it was otherwise, he would have been entitled to re-promotion w.e.f. the date of reversion i.e. 1-1-48 under the instruction No. 16 referred to above in the year 1949 itself. Capt. Kartar Singh and

his superior denied the applicability of that instruction No. 16 of 1949 to the workman by insisting that the reversion of the workman K. L. Sharma was on account of his inefficiency.

29. Originally, the reversion was on the request of the workman on account of fear that he may be retrenched if he did not agree to reversion, but in 1949 his Officer Capt. Kartar Singh made his reversion to rest on the ground of inefficiency, and the workman was penalised by not being given his original position, when juniors to him were repromoted as UDCs from back date.

30. The reference made to this Tribunal allows the Tribunal to examine his reversion w.e.f. 1-1-48 itself, and the Presidential Order of 9-10-68 does not bar examination of that order. This Tribunal is required by the Government of India to examine the justifiability of the action of the Government of India and the exercise is undertaken under I.D. Act 47 which is a Central Statute. The President of India is a Constitutional Head and acts on the advice of Ministers and other Officers subordinate to him and in accordance with the provisions of statutes made by Parliament. It is under a Mandate of the statutory provision in ID Act 47 that this Industrial Tribunal undertakes examination of the Presidential-Order of 9-10-68, in fact it undertakes examination of the reversion made on 1-1-48 under the terms of reference.

31. I am clearly of opinion that the reversion of the workman w.e.f. 1-1-48 was, initially, on account a fear of reduction in establishment and the workman consented to that reversion on account of that fear. But the officers of the Management later in 1949 made that reversion to be on account of his inefficiency and denied him relief on that basis. They treated the reversion as one on account of inefficiency, with the result that the workman was penalised for no fault of his. The Presidential Order of 1968 is just a pointer that the reversion from 1-1-48 was invalid and inoperative.

32. The workman in para 4 of his affidavit has made certain allegations against Capt. Kartar Singh in the following terms :—

"Captain Kartar Singh the Officer in charge Arrears Section of ASC Records (Supply) was having communal approach and vindicative approach. Being non-sikh, I also became victim of the same. Once he withheld my increment for a period of six months without any rhyme or reason vide Daily Order Part II dated 21-9-50 marked as Exhibit AW-3/6. I sought intervention of the higher authority and as a result thereof the said order withholding my increment was got cancelled vide order dated 17-11-51 marked Exhibit M-3/7. Again he levelled a false allegation stating that I had raised false alarm regarding a hunger strike for which he awarded the punishment of "Reprimand" vide order dated 13-3-52 marked Exhibit AW-3/8 and the same was got cancelled vide order dated 11-12-54 with the intervention of higher authorities marked Exhibit AW-3/9. Again he directed me to vacate the Government family accommodation by 10-4-1950 knowing fully well that my wife was at that time in the advance stage of pregnancy and delivered a baby on 19-4-1950. The order dated 30-3-1950 directing me to vavate Government accommodation is Exhibit AW-3/10 and the order dated 12-5-1950 regarding the birth of my daughter is Exhibit AW-3/11."

33. The action of Captain Kartar Singh in 1949, whether actuated by communal consideration or for other reasons, was undoubtedly fradulent in converting the reversion of the workman in 1948 due to voluntary acceptance on account of threatened retrenchment into a reduction in rank caused by proved inefficiency. This was wholly unjust and cannot go unchallenged. Captain Kartar Singh's superior officer was misled by Captain Kartar Singh's report made to him in 1949 and the workman was deprived of his repromotion in the year 1949 itself and of consequential benefits thereafter incluing promotion in subsequent years. The wrong done to the workman is directly the result of fraud committed by Captain Kartar Singh and the mistake committed by his Supervisor Officer, under Captain Kartar Singh's influence. This is the reason why the Government of India in the written statement, after petti-fogging attempt in para 9, had to clearly contend in para 10 of that statement that workman was reverted in 1948 due to inefficiency a punitive act.

34. The order No. 24(24)/61/D(Lab) dated 9-10-1968 of the President refers to OM No. 9/49/54-RPS dated 25-4-1958 issued by Ministry of Home Affairs and that requires to be examined to see whether it is applicable or not. The said OM of 25-4-1958 is reproduced in Appendix 39 by workman and relates to reversion to lower posts due to administrative errors or ignorance of facts when reduction in establishment is made or there is normal cessation of vacancies. It relates to retrenchment or reversion due to non-observation of departmental instructions or due to erroneous interpretation of the instructions or due to wrong determination of seniority of the individual concerned. It does not refer to wilful wrong done to a workman or action taken against him which is based on mistake or fraud.

35. In the case of this workman Mr. K. L. Sharma the conduct of Capt. Kartar Singh was fraudulent in treating the reversion of Mr. K. L. Sharma as being based on inefficiency which in fact was not true, because the reversion was on account of workman's consent believing that there was threatened retrenchment in the cadras.

36. Mistake or fraud vitiate any action however solemn. In this case also the conduct of Capt. Kartar Singh, with whom the superior officer concurred, has played havoc with the career of this workman Mr. K. L. Sharma. Wrong has been done to Mr. K.L. Sharma in treating his reversion w.e.f. 1-1-1948 as punitive on account of his inefficiency, whereas in fact it was not so. The grievance of the workman is correct and treating his reversion as being punitive on account of inefficiency has caused him loss in salary, promotion and retirement-benefits.

37. Under the circumstances mentioned above, the O.M. of the Ministry of Home Affairs of 58 referred to above does not apply to this workman and it is a peculiar case of retrenchment on account of threatened reduction in establishment having been treated wilfully and wrongly as reversion on account of inefficiency, and the workman being victimised without opportunity of showing cause against it.

38. In view of what has been said in the foregoing, it is ruled that the retrenchment of the workman w.e.f. 1-1-1948 was unjustified and the OM of 58 referred to in the Presidental order of 9-10-1968 did not apply to him. The representative of the workman has referred to numerous cases namely AIR 1968 Allahabad 245, 1969 SLR 879 (SC), 1969 SLR 485(SC), 1970 SLR 257(Delhi), 1970 SLR 223(Delhi), 1971 SLR 779 (Delhi), 1970 SLR 166 (Mysore), 1970 SLR 48(Allahabad), 1971 SLR 257(Delhi) and 1971 SLR 578 at page 587 (Punjab & Haryana), where it is ruled that, when the reversion is held to be wrong the workman will be entitled to all benefits including loss of pay on the presumption that he was never reverted.

39. Accordingly I hold that the reversion of the workman w.e.f. 1-1-1948 was not correct and he should have been restored to his position as not reverted w.e.f. 1-1-1948 in the year 1949, itself and the decision taken by the Management that his reversion on account of inafficiency is wilfully false The workman is entitled to arrears of salary as well as the promotion benefits claimed by him, but he is disentitled to interest and is also disentitled to overtime-pay claimed by him. He shall get Rs. 76309.75p claimed by him as arrears of pay and allowances and Rs. 690.25p as cost of these proceedings total Rs. 77,000/- from the Management and it is ordered accordingly. He shall also get retiral benefits calculated on the new basis determined above. Interest shall be payable to him @12 per cent per annum on account allowed to him under this Award from date of enforcement of the award till payment to him.

40. The reversion w.e.f. 20-1-1949 was not pressed to be correct even by the Management and Presidential Order could not be varied by a Lower Authority subsequently.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

September 27, 1984.

[No. L-14012(1)/78-D.II(3)]

HARI SINGH, Desk Officer.

New Delhi, the 29th October, 1984

S.O. 3642.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhanora Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Charanpur, Disstt. Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd October, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 67 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhanora Colliery, Messrs Eastern Coalfields Limited, P.O. Charanpur, Dist. Burdwan.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of management—Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of workmen—Mr. A. K. Lalgupta, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(119)/82-D. IV(B) dated 22nd November, 1982 the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Agent, Bhanora Colliery Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Charanpur, District Burdwan in not designating Shri Premnath Vohra, Traffic as Traffic Incharge and placing him in Clerical Grade-I is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On a perusal of the above it is clear that the reference proceeds on the basis that the concerned workman Premnath Vohra was a traffic on the date of reference (22-11-82) and that he wanted to get himself designated as Traffic Incharge and to be placed in clerical grade I. Admittedly he was in clerical grade III upto 1978. Admittedly he was upgraded to the post of pit clerk in clerical grade II by an office order dated 17-5-79/20-11-79 (Ext. M-7) retrospectively with effect from 1-1-1979. This was done by reason of the policy decision of the management of the ECL (Ext M-4 dated 28 March 1979) which was enforced by a circular (Ext M-5 dated 23 April 1979). This upgradation to clerical grade II was done because of the undertaking given by the concerned workman Premnath Vohra dated 12/13-11-1979 (Ext M-6). He also received payment for April 1983 vide Ext M-8 salary sheet.

3. The question is as to whether or not the stand of the union that Sri Premnath Vohra should be designated as traffic incharge and should be placed in clerical grade I is correct. The answer must be in the negative. The union has not submitted any document nor it shown any rule for the entitlement of the concerned workman to the post of clerical grade I. I do not see on what basis he can be upgraded to that post. From the argument advanced on behalf of the union and also from its written statement it seems to me that claim for grade I is mainly based on the ground of long service of the concerned workman for 32 years and because of the nature of duty which the concerned workman claimed to have performed. I will refer to these two facts later on. Before that I would like to say that even the traffic incharge falls in the category of clerk in grade II and not grade I. The schedule to the reference proceds on mis-conception because as per schedule traffic incharge can be placed in grade I. But the traffic incharge will be in category II and not in category I. Since the Mazumder Award of 1956 upto NCWA-III in 1983 traffic incharge has been shown in grade II and not in grade. The Mazumder Award in para 796 and Appendix XVI has detailed the classification and designation. In that Appendix the designation of traffic incharge is clerical grade II. The same was accepted by the Coal Wage Board whose recommendations were approved by the Central Government on 15th August 1967. The wage board provided the categorisation of clerical staff as embodied in the Mazumder Award with certain exceptions with which we are not concerned. In NCWA-I (Ext M-8/a) the same grading and nomenclatures of the clerical staff was adopted. The JBCCI also published a booklet stating the grading and nomenclature of the clerical staff. It showed the traffics in grade II. NCWA-II came into force in 1979. This also accepted the grading a nomenclatures above mentioned. It will not be out of place to mention here that this agreement was in force when the present reference was made. I think that the Central Government in the Ministry of Labour overlooked this fact and made the reference. If the government would have been aware of this fact it would not have made the reference. In view of the Supreme Court decision in the case of Life Insurance Corporation, 1981-I-LLJ I which laid down that a dispute can be raised only after the termination of the settlement and not otherwise. In the year 1983 the third National Coal Wage Agreement (Ext M-9) came into force, this agreement also accepted the grading and nomenclatures as mentioned in the booklet of the JBCCI. Here also traffic incharge was shown in grade II. Thus traffic incharge has uniformally been shown in grade II and not in grade I right from the year 1956 upto the 1983. In this view of the matter it must be held that the reference proceeds on mis-conception of a vital fact, it assumes that Mr Premnath Vohra by being given the designation of traffic incharge will be entitled to grade I. The reference describes Premnath Vohra as traffic. I have already said that traffic was previously in grade III but on being upgraded with effect from 1-1-1979 it became grade II and it will not be very material now as to whether Premnath Vohra is designated as traffic or traffic incharge for the purposes of grading, because in either case he would be in grade II after 1st January 1979.

4. The striking feature of the case is that the concerned workman Premnath Vohra gathered courage to claim grade I even after giving undertaking on 12/13-11-1979 (Ext M-6). By that undertaking he accepted grade II and now he challenging the same through his union. He cannot be permitted to do so in view of the principles underlying the doctrine of estoppel. In his evidence (WW-1) he said that he signed the undertaking on the asking of the Welfare Officer; that is not believable, the welfare officer has not been examined. It is not his evidence that he did not understand the undertaking. In his evidence he said that he has not prepared Form-IV till date, that he has not issued any measurement slips nor he maintains any record of lead, lift pushing etc. These were the additional works which the upgraded workman had to do. The concerned workman denies to have done these additional works only in order to run away from the undertaking. In my opinion his denial is of no consequence. Suffice to say that he agreed to do these additional works by giving the undertaking. In my opinion he is bound by his undertaking and on this ground alone his claim for grade I is liable to be thrown out.

5. So far as the nature of duty is concerned the evidence of the concerned workman Premnath Vohra is :

"I supervise the stores i.e. timbers and other materials required to both the pits I also supervise the maintenance of tracks and tubes. I also expedite the output produces I also inspect load. I have to look after the work of about 40 workmen. (Ext W-1 shown to the witness). The occasion of issuing Ext W-1 the suspension of liftment of coal in tubs because of jamming of wheels for non-supply of oil by me to them when I was at some other place of my duty at No 4 level. I have been working in the Bhanora colliery since 1952. Besides the duty of traffic I do

the work of track maintenance, load inspection, material supply and placing of materials at proper places etc. I have been doing the same duty from the year 1952 and even in the present time I do the same."

This has been denied by the witnesses of the management A. K. Sengupta (MW-1 and G.C. Karmakar (MW-2). I am inclined to believe the witnesses of the management. There is no duty chart showing that these were the duties to be prformed by him. The management has filed salary sheet (Ext M-8), B Form Register, (Ext M-1), the undertaking (Ext M-6) given by the concerned workman and has also examined two witnesses aforesaid in order to prove that the concerned workman, never worked as traffic incharge. As already stated I accept the case of the management and hold that he was not doing the job of traffic incharge.

6. It was argued on behalf of the union that the concerned workman Prem Nath Vohra was in service from 1952, that he became an employee of the management of the ECL after nationalisation in 1973 and thus he has been in service for 32 years but he has not been properly graded. In my opinion the argument is not sound. He was originally a tub checker in the year 1952 when he was serving the erstwhile management. His identity card is Ext. W-2. That no doubt shows that he had been appointed in 1952 but it does not mean that he has not been placed in proper grade by the ECL. The concerned workmen will naturally be governed by the National Coal Wage Agreement and the fact of appointment in 1952 by tha erstwhile management is of no help to him. He was of course designated as pit clerk in grade II with effect from 1-1-79 by the ECL. I have no material to say that the said upgradation is wrong. The acceptance of that grading by Premnath Vohra himself (vide Ext. M-6) rather shows that he said upgrading was liked by him and so he accepted it voluntarily.

7. The concerned workman has filed only two documents Ext. W-1 and W-2. I have already said that Ext. W-2 is identity card showing that he was appointed in 1952. Ext. W-1 shows that he was a pit clerk. An explanation was called from him as to why the winding of No. 2 pit was stopped and what action he had taken while acting as pit clerk. I do not see how this document helps him.

8. It was next argued on behalf of the union that the principles of job fixation is 15 years. It was submitted that the job span for grade III was 15 years, for grade II also 15 years and for grade I also 12 years. I do not understand how this fact can be of any assistance to the concerned workman. At the time of nationalisation he was in clerical grade III. Only after 5 or 6 years he was upgraded to grade II with effect from 1-1-1979, 15 years have not passed thereafter. This submission therefore is of no use to the union.

9. In the result my concluded award is that the action of the Agent, Bhanora Colliery, Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Charanpur, District Burdwan in not designating Shri Premnath Vohra Traffic, as Traffic Incharge and placing him in Clerical Grade-I is justifiad. It follows that the concerned workman is not entitled to any relief.

Dated, Calcutta

10th October, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No L-19012(119)/82-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984